चीनी पर नए सिस्टम के लिए राज्यों को चाहिए वक्त

PDS शुगर से राज्यों का स्वाद कड़वा

[ईटी ब्यूरो *गुवाहाटी & नई दिल्ली*]

पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के लिए चीनी खरीदने में छूट देने का केंद्र सरकार का फैसला राज्यों को भारी पड़ रहा है। अभी तक केवल 5 राज्यों ने इसके लिए टेंडर निकाले हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही जम्मू-कश्मीर ने केंद्र से ऑल्टरनेटिव सिस्टम की मांग की है।

मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया, 'पूर्वोत्तर राज्यों को ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते ज्यादा मुश्किलें आएंगी। ये राज्य इंफ्रास्ट्रक्टर डेवलप करने के लिए पुरानी स्कीम का समय बढ़ाने के लिए कह रहे हैं।'

जून की शुरुआत से केंद्र सरकार पीडीएस के लिए मिलों से चीनी नहीं खरीदेगी। अब राज्यों को इसे ओपन मार्केट से टेंडर के जरिए खरीदकर सब्सिडाइज्ड रेट पर राशन की दुकानों पर बेचना होगा। केंद्र लॉस की भरपाई करने के लिए राज्यों को पैसा देगा। अभी तक 7 पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर सहित 18 राज्यों ने चीनी खरीदने के लिए टेंडर जारी नहीं किए हैं। दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने ही टेंडर दिए हैं।

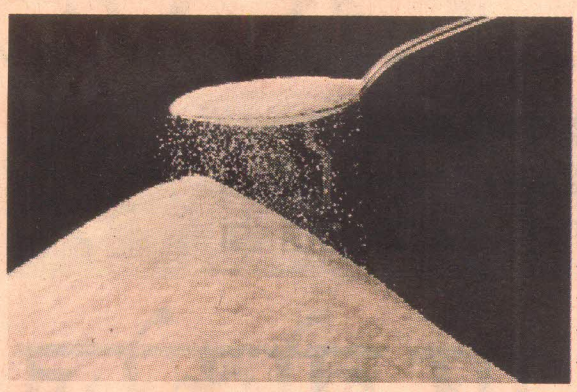

सिर्फ 5 राज्यों ने दिए टेंडर

अभी तक दिल्ली, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश ने इसके लिए टेंडर निकाले हैं और पूर्वोत्तर राज्यों के साथ ही जम्मू-कश्मीर ने केंद्र से ऑल्टरनेटिव सिस्टम की मांग की है

पूर्वोत्तर राज्य अभी तक लोडिंग प्वाइंट से राशन की दुकानों तक पीडीएस चीनी की स्टोरेज और सप्लाई के लिए एफसीआई की सर्विसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इन ज्यों ने केंद्र से इसे तब तक जारी रखने का आग्र किया है, जब तक वे नए सिस्टम के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर लेते।

असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने हाल ही में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर एफसीआई के जरिए पीडीएस के तहत चीनी की सप्लाई की मौजूदा व्यवस्था कम से कम एक साल के लिए जारी रखने को कहा था। एफसीआई के एक सीनियर ऑफिशियल ने बताया, 'अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नगालैंड में भी हालात असम जैसे हैं। सभी राज्यों ने जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए समय मांगा है और तब तक पुरानी व्यवस्था जारी रखने को कहा है।'

त्रिपुरा ने पीडीएस के जरिए बेची जाने वाली चीनी की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में हिस्सेदारी के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध किया है। राज्य सरकार का कहना है कि इससे चीनी के दाम बढ़ जाएंगे। जम्मू-कश्मीर ने भी केंद्र से यही बात कही है।

राज्य के सामने एक अलग समस्या है। रमजान का महीना और अमरनाथ यात्रा शुरू होने से चीनी की खपत काफी बढ़ जाती है। राज्यों को राशन की दुकानों पर चीनी 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम के रेट पर बेचने की स्थिति में केंद्र से 18.5 रुपए रुपए प्रति किलोग्राम की सब्सिडी मिलेगी।

उत्तर भारत में अभी चीनी की कीमत 30-32 रुपए जबकि महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में 29.5-31 रुपए प्रति किलो है।

Hindi Economic Times
28/5/13